इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 12 जुलाई 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
पूंजी बाज़ार----------5
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------5
बीमा ----------5
विदेशी मुद्रा ----------5
उत्पाद एवं गंठजोड़ ----------6
ग्रामीण बैंकिंग----------6
नयी नियुक्तियां----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------8
बाज़ार की खबरें----------8

2

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मध्य-तिमाही मौद्रिक नीति की समीक्षा - 18 जून 2012

मौद्रिक उपाय एवं चलनिधि उपाय

- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 4.75% पर अपरिवर्तित।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 8.0% पर अपरिवर्तित।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रति पुनर्खरीद (reverse repo) दर 7.0% पर अपरिवर्तित।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 9.0% पर।

वृद्धि

- आपूर्ति पक्ष से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और मांग पक्ष से कमजोर निवेश ने वृद्धि के धीमेपन में महत्वपूर्ण रूप से अंशदान किया। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल 0.1% की वृद्धि हुई।

मुद्रास्फीति

- वर्ष 2012-13 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अब तक मुख्यत: खाद्य और ईंधन की कीमतों से प्रेरित शीर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की दर अप्रैल में 7.2% के स्तर से मामूली तौर पर बढ़ कर मई में 7.6% पर पहुंची है।
- यद्यपि अप्रैल में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है, रुपये के मूल्यह्रास ने थोक कीमतों पर उसके प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से निष्प्रभ कर दिया है।

3

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति (नयी श्रृंखलाओं द्वारा यथा-मापित आधार वर्ष 2010) फरवरी के 8.8% से बढ़ कर मार्च में 9.4% और अप्रैल में 10.4% हो गया।
- वृद्धि में मंदी के बावजूद बढ़ता चालू खाते का घाटा (CAD) मांग-आपूर्ति असंतुलनों और आपूर्ति सम्बन्धी अड़चनों को दूर किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता का लक्षण-सूचक है।

चलनिधि की स्थितियां

- यद्यपि मुद्रा आपूर्ति (एम3) की वृद्धि अनुमानित प्रक्षेप-वक्र से मामूली कम रही, ऋण वृद्धि अनुमानित दर से अधिक के स्तर पर पहुंच गई। खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) ने चलनिधि की स्थिति को पर्याप्त रूप से सहज बना दिया है, जैसा कि एक-दिवसीय मांग मुद्रा दरों के नीतिगत पुनर्खरीद दर के आसपास स्थिर होने से प्रतिबिंबित होता है। चलनिधि को और आवर्धित करने तथा निर्यात क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात ऋण पुनर्वित्त की सीमा को बैंकों के बकाया निर्यात ऋण के 15% से बढ़ा कर 50% कर दिया है, जिससे संभाव्य रूप से 300 बिलियन रुपये से अधिक की अतिरिक्त चलनिधि प्राप्त होगी अर्थात् आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में लगभग 50 आधार अंकों की कटौती।

बाह्य क्षेत्र

- वर्ष 2011-12 के दौरान बिगड़ती वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों की पृष्ठभूमि में चालू खाते के बढ़ते घाटे के कारण रुपये पर अधोगामी (हानिकारक) दबाव पड़ा। चूंकि पूंजीगत अन्तर्वाह में धीमेपन की प्रवृत्ति जारी है, अप्रैल से रुपये के मूल्य में और भी गिरावट आई है। अंत में विक्षोभपूर्ण वैश्विक स्थिति को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी प्रतिकूल घटना का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों एवं उपायों का त्वरित एवं उपयुक्त रूप से उपयोग करने हेतु तैयार है।

मुख्य घटनाएं

बैंकों के जिंस वायदा व्यापार में प्रवेश को सरकार की मंजूरी

सरकार ने बैंकों के जिंस वायदा व्यापार में प्रवेश को विधिसम्मत बनाने हेतु मन बना लिया है। वर्तमान में, बैंक शेयरों, बॉण्डों और मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं, किन्तु बैंककारी विनियमन अधिनियम की

4

धारा 8 उन्हें माल का व्यापार करने से निषिद्ध करती है। अब वित्त मंत्रालय ने बैंकों को बचाव व्यवस्था का एक साधन उपलब्ध कराने में सहायता करने हेतु उक्त कानून को संशोधित करने के उपभोक्ता मामला मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन किया है। वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 सभी कम्पनियों को पण्य वायदों के व्यापार में सहभागिता करने की अनुमति देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस क्षेत्र में बैंकों के प्रवेश का विरोध करता रहा है, क्योंकि देश में कोई "स्वायत्त एवं स्वतंत्र" पण्य विनियामक मौजूद नहीं है।

अस्थिर दर वाले गृह ऋणों पर समय-पूर्व अदायगी प्रभार समाप्त करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अस्थिर दर वाले गृह ऋणों पर मोचन निषेध प्रभारों (समय-पूर्व अदायगी प्रभारों) को समाप्त करने (प्रचलन से हटाने) का निदेश दिया है। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा और नये उधारकर्ताओं के बीच भेदभाव में कमी आएगी तथा बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप अस्थिर दर वाले गृह ऋणों की अपेक्षाकृत अधिक अच्छी कीमतें निर्धारित होंगी।

वित्तीय समावेशन के पाश में और लोग शामिल होंगे

सरकार वित्तीय समावेशन के गोलखंभे (goalpost) में जनसंख्या के एक अपेक्षाकृत व्यापक वर्ग को उस बैंकिंग पाश में शामिल करने हेतु बदलाव करेगी जिससे रिसावों को रोकने और मंद पड़ती अर्थव्यवस्था में अधिक बचतें सृजित होने की आशा की जाती है। बैंकों से बैंक शाखाओं अथवा कारबार संपर्कियों (BCs) के माध्यम से अपना प्रसार-क्षेत्र 1,600 और उससे अधिक (पूर्ववर्ती 2000 की तुलना में) की जनसंख्या वाले गांवों तक फैलाने के लिए कहा गया है। बैंकों को इस परियोजना को मार्च 2013 तक पूरी कर लेने के निर्देश दिए गए हैं।

छात्र ऋणों से सम्बन्धित ऋण गारंटी निधि के लिए 5000 करोड़ रुपये की मूल निधि

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित ऋण गारंटी निधि की मूल निधि 5000 करोड़ रुपये होगी। उक्त निधि 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋणों को किसी प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूति और अन्य पक्ष की गारंटी के बिना सुरक्षित करेगी तथा चूक की स्थिति में 75% तक की गारंटी प्रदान करेगी। भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा तैयार की गई वर्तमान मॉडेल शिक्षा ऋण योजना में 4 लाख रुपये से अधिक वाले ऋणों को अन्य पक्ष की गारंटी के रूप में प्रतिभूत किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 1 जुलाई से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्राहकों, कर्मचारियों, विक्रेताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं को सभी भुगतान और उसके साथ ही ऋणों का संवितरण तथा निवेश के रूप में भुगतानों को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से करने के अनुदेश दिए हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक

5

भुगतान को प्रचलित करने और चेकों के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेनों की संख्या घटाने के लिए किया जा रहा है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बैंकिंग क्षेत्र के लिए नयी नीतिगत रूपरेखा

वित्त मंत्रालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), सहकारी बैंकों तथा अन्य क्षेत्रीय बैंकों को अगले स्तर तक विकास करने में समर्थ बनाने हेतु भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए नया नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक उस ढांचे पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जिसमें लाभ, पूंजी पर्याप्तता, आकार और ऐसी अन्य शर्तें निर्धारित की जाएंगी, जिन्हें वह ऐसी संस्थाओं को स्वयंपूर्ण बैंक बनने के लिए उचित समझे। इस प्रकार की नीति यह सुनिश्चित कर सकती है कि इन संस्थाओं के पास स्वयं उनकी वृद्धि योजना के अनुरूप सुस्पष्ट कार्य-निष्पादन के न्यूनतम मानदंड मौजूद हों।

मूलभूत सुविधा वित्त कम्पनियों के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह घोषणा की है कि सभी मूलभूत सुविधा वित्त कम्पनियां (IFCs) निजी-सरकारी सहभागिता (PPP) और परियोजनाओं के समावेश वाले बॉण्डों पर 50% का जोखिम भार लागू कर सकती हैं। इस मुहिम का उद्देश्य मूलभूत सुविधा वित्त कम्पनियों को जोखिम-भार की दृष्टि से मूलभूत सुविधा ऋण निधि - गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (IDF-NBFC) के समकक्ष लाना है।

सहकारी बैंक मीयादी जमा परिवर्तन मानदंड निर्धारित कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को ग्राहकों द्वारा उच्चतर ब्याज दरें प्राप्त करने के लिए मीयादी जमाराशियों के अन्य जमा योजनाओं में समय-पूर्व परिवर्तन की प्रथा को रोकने के लिए नीति बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह बेहतर आस्ति-देयता प्रबन्धन को सुगम बनाने के लिए किया गया है।

अदावीकृत खातों के सम्बन्ध में नीति तैयार करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) से अदावीकृत जमाराशियों अथवा निष्क्रिय खातों वाले ग्राहकों का पता लगाने हेतु नीतियां तैयार करने के लिए कहा है, ताकि

उनके लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ किया जा सके। इन नीतियों में अदावीकृत जमाराशियों के वर्गीकरण, शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु परिवाद निवारण व्यवस्था, रिकार्ड रखने तथा ऐसे खातों की आवधिक समीक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

6

विशिष्ट परिचय कूट के सम्बन्ध में बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए उनके नये और उसके साथ ही मौजूदा ग्राहकों को 31 मई 2013 तक विशिष्ट परिचय कूट प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कूट से अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंडों के सुदृढ़ प्रवर्तन में सहायता प्राप्त होगी और बैंकों को ग्राहकों को पहचानने, प्राप्त की गई सुविधाओं का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।

सफेद लेबल वाले एटीएमों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में सफेद लेबल वाली स्वाचालित टेलर मशीनों (WLATM) के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। सफेद लेबल वाला एटीएम गैर-बैंकिंग कम्पनियों / संस्थाओं द्वारा स्थापित किया जा सकता है और वह बैंकों द्वारा जारी कार्डों (डेबिट / क्रेडिट / पूर्वदत्त) के आधार पर भारतीय बैंकों के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। सफेद लेबल वाले एटीम प्रचालक की भूमिका सभी बैंकों के ग्राहकों के लेनदेनों की प्राप्ति तक सीमित होगी और इसलिए उन्हें मौजूदा एटीएम नेटवर्क प्रचालकों के साथ तकनीकी संयोजकता स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

ऋण संपार्श्विकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश से कम्पनियां प्रभावित होंगी

ऋण संपार्श्विकों में कमी से बैंकों को बचाने के लिए सृजित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश से मंदी से प्रभावित उन कम्पनियों को ऋण प्रवाह की स्थिति खराब होने का खतरा उपस्थित हो गया है, जो वेतन और सांविधिक देय राशियों के भुगतान में पिछड़ती जा रही हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उनकी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में इस प्रकार के अनुपालन के लिए लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए हैं कि उधारकर्ताओं के जिम्मे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदानों जैसी सांविधिक देय राशियां बकाया न हों। इसप्रकार की रुकावटें बैंकों के हित में होंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवक विप्रेषणों से सम्बन्धित सीमाएं बढ़ाईं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले विदेशी विप्रेषणों की संख्या प्रति कैलेंडर वर्ष 12 से बढ़ा कर 30 कर दी है। हालांकि, प्रत्येक लेनदेन की रकम पर सीमा प्रति व्यक्ति 2,500 अमरीकी डालर के रूप में अपरिवर्तित रखी गई है। इस उपाय से उन विप्रेषकों को, जो बार-बार धनराशि विप्रेषित करते हैं तथा उन लोगों को भी लाभ पहुचने की आशा है, जिनके पास विदेशों से धनराशि प्राप्त करने के बहु-विध स्रोत हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

7

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 'यूएसबी' अभियान

अत्यंत लघु शाखाएं अर्थात यूएसबी खोलना अब इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मंत्र बन गया है। जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम कार्यान्वित कर दिया है, ऐसे 900 से अधिक गांवों में अति लघु शाखाएं मौजूद हैं। पिछले कुछेक वर्षों से बैंक एक विनियामक अधिदेश के एक अंग के रूप में बैक-रहित गांवों तक पहुंचने के प्रयास करते रहे हैं। अति लघु शाखाओं के खुलने के परिणामस्वरूप नकदी प्रबन्धन, प्रलेखीकरण, ग्राहक परिवाद निवारण तथा कारबार संपर्की (BC) परिचालन पर गहन पर्यवेक्षण में कुशलता आने की आशा है।

बैंकों में एकसमान परिवाद निवारण प्रणाली शीघ्र ही

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से तीन माह के भीतर एकसमान III स्तरीय परिवाद निवारण प्रणाली लागू करने के लिए कहा है। यह मुहिम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी ग्राहक शिकायतों का निराकरण 21 दिनों के भीतर कर दिया जाए। बैंकों से परिवाद को आंतरिक प्रणाली को सुधारने के एक अवसर के रूप में लेने और उसके द्वारा ग्राहक को टिकाए रखने तथा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कहा गया है।

इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण नि:शुल्क हो सकता है

सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एक ऐसी रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा है जिसके तहत निधियां एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक विधि से नि:शुल्क अंतरित की जा सकें। वर्तमान में बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (NEFT) और तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) के माध्यम से निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए 5 रुपये से लेकर 55 रुपये तक वसूल करते हैं। लागत-रहित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन ग्राहकों को पूरे देश में अंतर-बैंक और उसके साथ ही अंत:-बैंक निधि अंतरण के लिए इस माध्यम का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इससे नकदी लाने-ले जाने और नकदी लेनदेन में कमी लाने भी सहायता प्राप्त होगी।

मोबाइल बटुओं के सम्बन्ध में बैंको को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है

कई एक बैंकों, प्रौद्योगिकी कम्पनियों तथा दूरसंचार सेवा-प्रदाताओं द्वारा मोबाइल बटुओं की तलाश की जा रही है। बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड नेटवर्क के माध्यम से धनराशि को क्रेताओं से विक्रेताओं तक पहुंचाने के कार्य में अच्छी कमाई करते हैं, किन्तु स्मार्ट फोन भुगतान उस व्यवसाय को काफी

पीछे छोड़ सकते हैं। 600 से अधिक उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि उनमें से 48% मोबाइल बटुओं अथवा उस प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले थे, जो स्मार्ट फोनों को भुगतान उपकरणों में रूपांतरित कर देती है। उनमें से 53% ने उनके मूल बैंक की तुलना में वैकल्पिक सेवा-प्रदाता को

8

तरजीह दी। भुगतान व्यवसाय को यह प्रतिस्पर्धात्मक खतरा इसलिए पैदा हुआ क्योंकि बैंकों ने ऐसे नये विनियमों को अपनाया है, जो उस "अंतर-परिवर्तन शुल्क " को दबा देते हैं जो वे व्यापारी से उस समय वसूल करते हैं, जब उपभोक्ता डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं।

बैंक बंधक रखी गई सम्पत्ति की नीलामी करके ऋण वसूल कर रहे हैं

बैंक अब अपनी प्राप्य राशियों को वसूल करने हेतु वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेयसी) अधिनियम 2002 का उपयोग करने का अधिकाधिक रूप से आश्रय ले रहे हैं। उक्त अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उधारकर्ताओं के उनके ऋण चुकाने में विफल हो जाने पर बंधक रखी गई निवासीय / वाणिज्यिक सम्पत्ति की नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है। जब अर्थव्यवस्था तेजी पर थी उस समय अधिनियमित उक्त अधिनियम का उपयोग अपेक्षाकृत छोटी प्राप्य राशियों को वसूल करने हेतु बहुत कम किया जाता था, इसका उपयोग 1 लाख रुपये से अधिक के किसी भी ऋण / प्राप्य राशियों के लिए किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लाभांश का भुगतान करने से छूट दी जा सकती है

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक एकल नियंत्रक कम्पनी का गठन करने के अपने अभियान के एक अंग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उसे लाभांश का भुगतान करने से छूट प्रदान कर सकती है। सभी बैंकों के प्रतिधारित अर्जनों का पुन: प्रयोग उस ऋण तथा उक्त ऋण पर ब्याज चुकाने हेतु किया जाएगा, जो यह नियंत्रक ढांचा बैंकों के लिए जुटाएगा।

बैंकों को जिल्टों में सांकेतिक मंदड़िया बिक्री करने की अनुमति

बैंक अब उनके द्वारा 'व्यापार के लिए धारित' (HFT) श्रेणी में धारित सरकारी प्रतिभूतियों (G-srcs) की खरीद से अधिक बिक्री (short positions) कर सकते हैं। ऐसे विविध परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें कोई सहभागी 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी के तहत विशिष्ट प्रतिभूतियों की साथ-साथ 'बिक्री से अधिक खरीद' और 'खरीद से अधिक बिक्री' वाली स्थिति में आ जाता है, वहां अब 'व्यापार के लिए धारित' पोर्टफोलियो से 'सांकेतिक' खरीद से अधिक बिक्री की अनुमति दी जाएगी। बैंक खरीद से अधिक बिक्री के समक्ष सुपुर्दगी के लिए व्यापार के लिए धारित पोर्टफोलियो के तहत मौजूदा बॉण्डों का उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें इसके पहले बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) और परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी में धारित सरकारी बॉण्डों में खरीद से अधिक बिक्री की अनुमति दी गई थी।

आधार-समर्थित खातों पर भारतीय रिज़र्व बैंक का रवैया

9

इलेक्ट्रॉनिक अंतरणों को सुगम बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के हिताधिकारियों के लिए आधार-समर्थित बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक यह चाहता है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे खाते 2000 से कम आबादी वाले गांवों के निवासियों के लिए खोले जाएं।

व्यवहार्यता सम्बन्धी चुनौतियों के बीच वित्तीय समावेशन प्रगति पर

सरकार की महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन योजना में गति आ रही है। नो फ्रिल्स खातों की संख्या 2010 में 4.93 करोड़ से दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 10.32 करोड़ हो गई है। बैंकों ने पिछले दो वर्षों में 3, 171 ग्रामीण शाखाएं खोली हैं। बैंकों द्वारा परिनियोजित कारबार संपर्कियों / कारबार संपर्कियों के एजेन्टों की संख्या में लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई, जो 2010 में 33, 042 के स्थान पर 2012 में 96, 828 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक हिताधिकारी अंतरण (EBT) खातों की संख्या 2010 में 74.8 लाख से बढ़ कर 2012 में 2.17 करोड़ हो गई। हालांकि, नो फ्रिल्स खातों की व्यवहार्यता अधिकांश बैंकों के लिए एक चिंता रही, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में खाते गैर-परिचालनीय हैं। इसके अलावा, कुछेक खातों में अल्प-मूल्य वाले लेनदेनों का परिमाण अधिक रहा, जिसका बैंकों के लिए लागत सम्बन्धी निहितार्थ था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों के विषय क्षेत्र को व्यापक बनाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि महाविद्यालयीन शुल्कों, विद्यालयीन शुल्कों तथा सरकारी करों का भुगतान करने हेतु अर्ध-सीमित प्रणाली वाले भुगतान लिखतों का भी 10,000 रुपये की सीमा तक प्रयोग किया जा सकता है। ये लिखत जारीकर्ता द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (KYC) की विहित कर्तव्यपरायणता कार्यविधि का अलग से पालन किए बिना जारी किए जा सकते हैं। अर्ध-सीमित प्रणाली वाले भुगतान लिखत सुस्पष्ट रूप से अभिज्ञात व्यापारिक स्थलों अथवा स्थापनाओं के उस समूह में प्रतिदेय होते हैं जिन्होंने इन भुगतान लिखतों को स्वीकार करने हेतु जारीकर्ता के साथ विशिष्ट रूप से संविदा कर रखी हो।

आगामी छ: महीनों में प्रति परिवार कम से कम एक बैंक खाता

एक महत्वाकांक्षी अभियान में वित्त मंत्रालय ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आगामी छ: माह में पूरे देश में प्रति परिवार कम से कम एक व्यक्ति का बैंक खाता हो। वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री सुनील सोनी का कहना है कि "इससे सरकार और उसकी एजेन्सियों

को मजदूरियों, वेतनों अथवा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण करने में सहायता प्राप्त होगी। रिसाव को कम करने के लिए सरकार की ओर से सभी भुगतान सीधे खाते में इलेक्ट्रॉनिक विधि से किए जाएंगे। 1 लाख रुपये से कम के इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण राष्ट्रीय

10

इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणाली के माध्यम से किए जाने की हाल ही की मुहिम के साथ उक्त निर्णय से निधियों की सस्ती आवा-जाही संभव हो सकेगी।"

विनियामकों के कथन

भारी सरकारी उधार से निजी क्षेत्र को ऋण में कमी हो सकती है

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा भारी मात्रा में उधार लिये जाने से निजी क्षेत्र को ऋण में कमी हो सकती है। "राज्य सरकारों द्वारा बाज़ार से लिये गए उधारों में भी वृद्धि हुई है, जो केन्द्र द्वारा ली गई भारी और बढ़ती हुई उधार राशियों के साथ एक संकटापन्न पुंज का रूप लेती जा रही हैं। अतएव, चलनिधि पर दबाव और उसमें ह्रास से बचने के लिए समन्वित ऋण प्रबन्धन की आवश्यकता है।"

कमजोर मूलभूत तत्वों से प्रेरित होने पर रुपये की गिरावट नहीं रोकी जा सकती

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी चक्रवर्ती ने कहा है कि "यदि रुपये में गिरावट अर्थव्यवस्था की मूलभूत कमजोरी के कारण है अथवा वैश्विक कारकों के आधार पर है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक उसे सहारा नहीं दे सकता। रुपये में गिरावट कमजोर मूलभूत तत्वों के कारण होने पर सरकार को व्यापार घाटे से जुड़े मुद्दों का निराकरण अवश्य करना चाहिए। यदि रुपये में मूल्यह्रास संपदा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के कारण हो रहा है, तो वित्तीय क्षेत्र के उपाय उसे हल नहीं कर सकते।" अप्रैल से सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं, विशेषत: अमरीकी डालर के समक्ष रुपये के मूल्य में गिरावट आ रही है और वह 1 जून, 2012 को 56.52 रुपये के अब तक के सबसे न्यून स्तर पर आ गया। उसमें आज के दिन तक लगभग 24% की कमी आई है। उन्होंने डालर की मांग को नियंत्रित करने तथा रुपये को सहारा देने में सहायता करने के लिए तेल कम्पनियों के लिए एक अलग खिड़की खोले जाने का भी संकेत दिया।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पर नीतिगत दरों में वृद्धि के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी चक्रवर्ती ने कहा है कि "सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मंदी के लिए केवल उच्च नीतिगत दरों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उससे अन्य कारक भी जुड़े हैं। मैं यह नहीं सोचता कि हमारी ब्याज दरें अथवा नीतिगत दरें इतनी अधिक हैं कि वे

वृद्धि को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकें। वृद्धि नीतिगत दरों के अलावा कई प्रकार के कारणों से प्रभावित हो रही है। वृद्धि पर नीतिगत दरों में वृद्धि के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है।

11

अधिसंख्य लोग व्यवसाय करने के लिए 13-14% पर उधार ले रहे हैं। निवेश का वातावरण सहायक न होने पर ब्याज दरों में 1-2% की कमी करने से वृद्धि में उछाल नहीं आने वाला है।"

खुदरा ऋण में तेजी से बचत दर कम हो सकती है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण के नेतृत्व वाले एक कार्य दल ने यह चेतावनी दी है कि खुदरा ऋण में तेजी की प्रवृत्ति देश की स्थिर बचत दरों को उच्चतर आर्थिक वृद्धि के बावजूद अस्थिर कर सकती है। खुदरा ऋण की बढ़ती पैठ, जो उपभोक्ताओ को भावी आय की प्रत्याशा में खर्च करने के लिए प्रेरित करती है, के कारण बचत दर के गतिहीन अथवा यहां तक कि कमतर होने का अधोगामी (हानिकर) जोखिम उपस्थित हो जाएगा।

पूंजी बाज़ार

अनिवासी भारतीयों के लिए नया निवेश मार्ग संभव

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) विदेशी अर्हताप्राप्त निवेशक (QFI) ढाचे में ऐसा स्पष्टीकरण करने की तैयारी कर रहा है जो अनिवासी भारतीयों को भारतीय शेयर बाज़ारों में निवेश करने में समर्थ बनाएगा। इसके पीछे निहित विचार निवेश करने की ताक में बैठे नये अनिवासी भारतीयों का दोहन करना है। हालांकि, ऐसे लोग जिन्होंने मौजूदा प्रावधानों के माध्यम से पहले से निवेश कर रखा है तथा अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक मार्ग अपनाने के इच्छुक हैं, उन्हें मौजूदा खाते बंद करने होंगे। उक्त स्पष्टीकरण प्रावधानों को पारदर्शी और अधिक निवशकोनुकूल बनाने के लक्ष्य से व्यापक दस्तावेज़ के एक अंग होंगे।

सेबी 1000 करोड़ से कम पण्यावर्त वाले शेयर बाज़ारों की मान्यता रद्द करेगा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने घोषणा की है कि 1000 करोड़ रुपये से कम के वार्षिक पण्यावर्त वाले शेयर बाज़ार स्वैच्छिक निर्गमन के पात्र हैं। गैर-मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों के लिए दो महीनों के भीतर निर्गमन हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा। ऐसा न किए जाने का परिणाम उनके अनिवार्य निर्गमन के रूप में सामने आएगा।

सेबी कारपोरेट अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ करेगा

भारत के कारपोरेट अभिशासन मानकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) घरेलू मानदंडों को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुरूप बनाएगा। भारतीय कारपोरेट अभिशासन मानदंडों को आर्थिक

12

सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा पुष्ट 6 सिद्धांतों के अनुरूप बनाने के सम्बन्ध में दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इनमें एक प्रभावी कारपोरेट अभिशासन ढांचे का आधार सुनिश्चित करना, शेयरधारकों के अधिकारों, शेयरधारकों के साथ समान व्यवहार, कारपोरेट अभिशासन में शेयरधारकों की भूमिका, प्रकटन एवं पारदर्शिता और निदेशक मण्डल के उत्तरदायित्वों का समावेश है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

1998 से ब्रिक राष्टों की मुद्राएं सर्वाधिक मूल्यह्रासित हुईं

सबसे बड़े उभरते बाज़ार, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं पिछले दशक में चार गुने से भी अधिक बढ़ीं, उनमें से प्रत्येक को खोने वाला बना रहे हैं, क्योंकि उनकी मुद्राओं में कम से कम 1998 से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। 13 वर्षों में पहली बार रियाल, रूबल और रुपया विकासशील देशों के बीच सर्वाधिक कमजोर पड़ते जा रहे हैं, जबकि युआन 1994 से किसी भी अन्य अवधि के मुकाबले सर्वाधिक मूल्यह्रासित हुआ है।

बीमा

इर्डा ने 'अनाथ' पॉलिसियों के सम्बन्ध में मानदंड जारी किए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने कहा है कि बीमा कम्पनियों को किसी भी व्यपगत 'अनाथ' जीवन बीमा पॉलिसी को पॉलिसी धारकों को प्रभावी सेवा प्रदान करने हेतु वैध लाइसेंस वाले अन्य वैयक्तिक बीमा एजेन्ट को आबंटित करने की अनुमति है। जीवन बीमाकर्ताओं को सम्बन्धित पॉलिसी धारक को नव-आबंटित एजेन्ट के विवरण सूचित कर देने चाहिए। उक्त 'आबंटिती एजेन्ट' द्वारा पॉलिसी से सम्बन्धित सभी सेवाएं ठीक उसी प्रकार प्रदान की जाएंगी जिस प्रकार बीमा एजेन्ट प्रदान किया करता था। 'अनाथ' जीवन बीमा पॉलिसियों से अभिप्राय है किसी ऐसे वैयक्तिक बीमा एजेन्ट द्वारा प्रारंभ कराई गई पॉलिसियां, जिसकी सेवाएं कालांतर में समाप्त, बर्खास्त अथवा बीमाकर्ताओं की सूची से विलुप्त कर दी गई हों।

सभी पेंशन योजनाओं में वार्षिकी अपरिहार्य

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री जे. हरि नारायण ने कहा है कि जीवन बीमाकर्ताओं को ऐसे मामलों में भी तात्कालिक अथवा आस्थगित वार्षिकी प्रदान करनी होगी जहां पेंशन उत्पाद न्यागमन तिथि से पहले अभ्यर्पित कर दिए जाते हों। अभ्यर्पण अथवा न्यागमन के

13

समय पॉलिसी धारक को जिसने मूल पेंशन पॉलिसी बेची थी उसी बीमाकर्ता से एकल प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी अथवा आस्थगित वार्षिकी उत्पाद खरीदना होगा।

विदेशी मुद्रा

जुलाई 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.06800	0.548	0.630	0.781	0.970
जीबीपी	1.68025	0.9971	1.0276	1.1320	1.2821
यूरो	1.18679	0.878	0.982	1.146	1.336
जापानी येन	0.55229	0.344	0.349	0.370	0.410
कनाडाई डालर	2.03950	1.252	1.339	1.431	1.542
आस्ट्रेलियाई डालर	4.55200	3.213	3.285	3.515	3.620
स्विस फ्रैंक	0.38200	0.135	0.145	0.232	0.351
डैनिश क्रोन	1.15250	0.7830	0.9120	1.0950	1.3120
न्यूजीलैंड डालर	3.44800	2.760	2.930	3.095	3.255
स्वीडिश क्रोनर	2.80000	1.890	1.939	2.005	2.102

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**22 जून 2012 के दिन**	**22 जून 2012 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	16, 434, 2	288,627 7

क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14 577. 0	255,783. 1
ख) सोना	1, 443, 5	25, 585.0
ग) विशेष आहरण अधिकार	249, 1	4, 370.7
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	164.6	2, 888.9

14

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक रुपया वायदे में बारंबार हस्तक्षेप करता है

व्यापारियों का कहना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संभवत: विदेशी मुद्रा की अपनी प्रारक्षित निधि की पुन: पूर्ति करने तथा घरेलू रुपया चलनिधि को प्रतिस्थापित करने के लिए हाजिर रुपये को बचाने के अपने प्रयासों के साथ रुपया वायदा बाज़ारों में अधिकाधिक रूप से हस्तक्षेप करता रहा है। आयातकों और विदेशी निवेशकों द्वारा अल्पावधिक प्रतिरक्षण की भारी मांग के साथ उस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप तटवर्ती और अपतटीय, दोनों ही दोनों ही स्तरों पर डालर / रुपया वायदा वक्र में भारी क्रम विपर्यय हुआ है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
आईसीआईसीआई और येस बैंक	मलेशियाई एक्जिम बैंक	दोनों देशों के बीच व्यापार, विशेष रूप से खजूर , खजूर तेल में व्यापार बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ बहरीन	अधिकाधिक सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों विनियामकों के बीच पर्यवेक्षी सूचना में हिस्सेदारी करना
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	एसबीआई जेनरल इंश्योरेंस	बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए
जियोजित बीएनपी परिबास फ इनैंसियल सर्विसेज	भारतीय स्टेट बैंक	अनिवासी भारतीयों को पोर्टफोलियो निवेश सेवाएं प्रदान करना
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान आयोग	रूपे कार्डों का बीमा और देश के अन्य बैंकों द्वारा जारी सभी रूपे कार्डों का भुगतान करना

ग्रामीण बैंकिंग

मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 632 करोड़ रुपये के पूंजी निषेचन को मंजूरी दी

15

पूंजी पर्याप्तता और कृषि क्षेत्र को उधारदायी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से संघीय मंत्रिमंडल ने नकदी की कमी से पीड़ित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 632 करोड़ रुपये के पूंजी निषेचन (केन्द्रीय सरकार के 50% अंश) को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। केन्द्रीय सरकार के अंश का जारी किया जाना राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के अंश के जारी किये जाने की शर्त पर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में केन्द्रीय और राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंकों द्वारा क्रमश: 50%, 15% और 35% के अनुपात में हिस्सेदारी की जाती है।

नयी नियुक्तियां

- श्री आलोक मिश्र को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- श्री एस. आर. बंसल को पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री पी. श्रीनिवास को बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री सुधीर कुमार जैन को बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री ए. तिवारी को इलाहाबाद बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री बी. पी. शर्मा को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री एस. डी. आर्य को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री के. रामदास शेणाय को विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री श्रीनाथ बोलोजू को ड्यूश बैंक इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री दिनेश कुमार मेहरोत्रा ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

दबाव परीक्षण (पिछले अंक से जारी)

16

जहां दबाव परीक्षण बिगड़ती आर्थिक स्थितियों को संभालने के लिए आवश्यक पूंजी के उपयुक्त स्तर का संकेत करते हैं, वही कोई बैंक बढ़ते हुए जोखिमों के स्तर को कम करने मे सहायता के लिए अन्य कार्रवाइयों का भी उपयोग कर सकता है। दबाव परीक्षण एक ऐसा साधन है जो जोखिम प्रबन्धन के अन्य दृष्टिकोणों एवं उपायों में सहायता करता है। यह निम्नलिखित में विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है :

- जोखिमों का प्रगतिशील निर्धारण उपलब्ध कराना;
- मॉडेलों और पारंपरिक आंकड़ों की सीमाओं पर काबू पाना;
- आंतरिक एवं बाहरी संप्रेषणों को समर्थन प्रदान करना;
- पूंजी और चलनिधि आयोजना कार्यविधियों की जरूरतें पूरी करना;
- बैंक की जोखिम सहनशीलता के निर्धारण की सूचना देना; और
- जोखिम न्यूनीकरण के विकास अथवा दबावग्रस्त स्थितियों की समस्त श्रेणियों की आकस्मिकता योजनाओं को सुगम बनाना।

दबाव परीक्षण लम्बी अवधियों की ऐसी सुसाध्य आर्थिक एव वित्तीय स्थितियों में, जब नकारात्मक स्थितियों की धूमिल होती स्मृतियों के परिणामस्वरूप आत्मसंतुष्टि एवं जोखिम का न्यून मूल्य-निर्धारण हो सकता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह विस्तार की उन अवधियों के दौरान जब नवोन्मेषन के परिणामस्वरूप ऐसे नये उत्पाद विकसित होते हैं, जो शीघ्रतापूर्वक बढ़ते हैं तथा जिनके लिए हानि का सीमित अथवा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता, एक प्रमुख जोखिम प्रबन्धन साधन भी सिद्ध होते हैं।

बासेल-II ढांचे के स्तंभ-1 (न्यूनतम पूंजी आवश्यकता) के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे दबाव परीक्षण का कठोर कार्यक्रम लागू करने के लिए बाज़ार जोखिम पूंजी का निर्धारण करने हेतु आंतरिक मॉडेलों का उपयोग करें। इसीप्रकार, ऋण जोखिम के लिए उन्नत एवं बुनियादी आंतरिक रेटिंग पर आधारित (IRB) दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने आंतरिक पूंजी निर्धारणों की सुदृढ़ता तथा विनियामक न्यूनतम स्तर से अधिक पूंजी कुशनों का आकलन करने हेतु ऋण जोखिम दबाव परीक्षण करें। बासेल-II में यह भी अपेक्षा की गई है कि बैंक बैंकिंग बही में अपने ऋण पोर्टफोलियो को न्यूनतम स्तर पर दबाव परीक्षण के तहत लाएं। हाल के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला है कि बैंकों के दबाव परीक्षणों से संकट में पड़ने वाले उनके पूंजी के सुरक्षित भंडारों अथवा हानि से सम्बन्धित उनके वास्तविक अनुभवों की तुलना में हानि की बड़ी संख्याएं नहीं निकलीं। इसके अलावा, बैंकों के फर्म-व्यापी दबाव परीक्षणों में परिणाम निकालने के लिए प्रयुक्त परिदृश्यों की

अपेक्षा अधिक गंभीर परिदृश्य शामिल किए जाने चाहिए थे, जो प्रेक्षित वास्तविक दबावों के अधिक अनुरूप होते।
बासेल समिति ने इस अवधि में किए गए दबाव परीक्षणों की जांच करने के समय उद्योग के साथ बातचीत की थी तथा यह दस्तावेज़ उसी जांच का परिणाम है। वर्तमान संकट के आविर्भाव तथा मिलने वाले भावीं सबकों की परवाह न करते हुए इस दस्तावेज़ में संकट के दौरान दबाव परीक्षण के कार्यों का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन के आधार पर और इन प्रथाओं में सुधार लाने के प्रयास

17

में यह समिति बैंकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सुदृढ़ सिद्धांत तैयार करती है। इन सिद्धांतों में समग्र उद्देश्यों, अभिशासन, डिज़ाइन और दबाव परीक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ ही साथ अलग-अलग जोखिमों एवं उत्पादों के दबाव परीक्षणों से जुड़े मुद्दों का समावेश है।
सिफारिशों का उद्देश्य बैंकों की दबाव परीक्षण प्रथाओं तथा इन प्रथाओं के पर्यवेक्षी मूल्यांकन पर निर्भर रहना है। दबाव परीक्षण अपने आप में जोखिम प्रबन्धन की सभी कमजोरियों का समाधान नहीं कर सकता, किन्तु एक व्यापक दृष्टिकोण के एक अंग के रूप में इसे बैक के कारपोरेट अभिशासन तथा अलग-अलग बैंकों एवं वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन में एक अग्रणी भूमिका निभानी होती है।
"दबाव परीक्षण" को सामान्य रूप से बैंक के भीतर निर्णयन में सहायता करने हेतु गंभीर, किन्तु युक्तिसंगत परिदृश्य में किसी बैंक की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के रूप में वर्णित किया जाता है। दबाव परीक्षण पद का प्रयोग न केवल अलग-अलग विशिष्ट परीक्षणों को लागू किए जाने की कार्यप्रणालियों, अपितु उस अपेक्षाकृत व्यापक परिवेश का भी का संकेत करने के लिए किया जाता है, जिसमे ये परीक्षण निर्णयन प्रक्रिया के भीतर विकसित, मूल्यांकित और प्रयुक्त किए जाते हैं। इस दस्तावेज में हम "दबाव परीक्षण" पद का प्रयोग इसी व्यापक अर्थ में करते हैं।
(स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

एक्सबीआरएल - विस्तरणीय व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा

एक ऐसा मानक जो वित्तीय डाटा जिस विधि से संप्रेषिति किया जाता है उसे अनुभाषित करना और बांटना अपेक्षाकृत आसान बनाते हुए सुधारने के लिए विकसित किया गया था। एक्सबीआरएल [विस्तरणीय मूल्यवर्धन (mark-up) भाषा] एक्सएमएल का एक प्रकार है, जो एक ऐसा विनिर्देशन है जिसका उपयोग डाटा को व्यवस्थित एवं परिभाषित करने हेतु किया जाता है। एक्सबीआरएल वित्तीय डाटा के प्रत्येक नग को पहचानने हेतु प्रचिन्हों (tags) का उपयोग करती है, जो उस स्थिति में उसे एक्सबीआरएल से सुसंगत क्रमादेशों में क्रमादेशित रूप में प्रयुक्त करने की अनुमति देता है।

शब्दावली

अर्ध-सीमित प्रणाली भुगतान लिखत

ये ऐसे भुगतान लिखत हैं जो सुस्पष्ट रूप से अभिज्ञात उन व्यापारी स्थलों / स्थापनाओं में प्रतिदेय होते हैं जिसने जारीकर्ता के साथ उक्त भुगतान लिखत को स्वीकार करने की विशिष्ट रूप से संविदा की हो। ये लिखत नकदी आहरण अथवा धारक द्वारा मोचन की अनुमति नहीं देते।

18

संस्थान की गतिविधियां

आईआईबीएफ, लीडरशिप सेंटर में जुलाई - सितम्बर, 2012 की तिमाही के लिए नियोजित प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	सहकारी बैंकों के लिए खज़ाना और जोखिम प्रबन्धन	16 से 18 जुलाई
2	लघु एवं मध्यम उद्यमों का वित्तीयन	23 से 27 जुलाई
3	सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा - कार्यशाला	4 अगस्त
4	खुदरा बैंकिंग उत्पादों का वित्तीयन एवं विपणन	6 से 10 अगस्त
5	अनुपालन कार्य- कार्यशाला	24 अगस्त
6	व्यापार वित्त	3 से 7 सितम्बर
7	संपदा प्रबन्धन	10 से 12 सितम्बर

आईआईबीएफ - विज़न का ई-मेल द्वारा प्रेषण

संस्थान अक्तूबर 2012 के बाद से आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजेगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, यदि वे पहले न पंजीकृत कराए गए हों, तो तत्काल पंजीकृत करा लें। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

संस्थान समाचार

साधारण सदस्यता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

संस्थान ने 18 जून, 2012 से साधारण सदस्यता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ कर दिया है। इसके बाद से संस्थान पंजीकरण हेतु सदस्यता फार्म और मांग ड्राफ्ट नहीं स्वीकार करेगा। अभ्यर्थियों

19

से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

इसके अलावा, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा शुल्क विप्रेषित करने हेतु ऑनलाइन भुगतान विधि का उपयोग करें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

91
86
81
76
71
66
61
56
51
46

01/06/12 04/06/12 07/06/12 08/06/12 12/06/12 18/06/12 19/06/12 21/06/12 26/06/12 28/06/12 29/06/12

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 31 मई को उथले बाज़ार में रुपया प्रचंड गति से गिरा और वह अमरीकी डालर के मुकाबले 54.96 के नये न्यून स्तर पर पहुंच गया।

- 7वीं को रुपया डालर के समक्ष दो सप्ताह के उच्च स्तर से अधिक 54.95 पर बंद हुआ।
- 12वीं को रुपया लगभग एक सप्ताह के अंत:-दिवसीय न्यून स्तर 56.08 पर पहुंच गया, क्योंकि 55.80 पर स्थिर होने के पहले कम्पनियों से डालर की मांग बढ़ गई। उस दिन रुपये के कुछ हानियों की भरपाई करने में सहायता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई देखने में आई।
- यूरो के मजबूत होने के बीच अंतिम क्षण में डालर की बिक्री के कारण 13वी को रुपये ने 12 पैसे अधिक अर्थात 55.68 के स्तर पर बंद होकर तीन दिन के गिरावट वाले दौर को समाप्त कर दिया।
- न्यूनता के लगभग रिकार्ड पर स्थिर रहते हुए 27वीं को रुपया लुढ़क गया, क्योंकि तेल आयातकों ने माह के अंत में अपनी

डालर खरीद की मुहिम तेज कर दी। रुपया अब तक के सबसे कम स्तर 57.15 पर पहुंच गया।
- माह के दौरान, रुपया डालर के मुकाबले 0.7%, स्टर्लिंग के मुकाबले 2.35% और यूरो के मुकाबले 2.5% मूल्यह्रासित हुआ, जबकि जापानी येन के मुकाबले 0.5% मजबूत पड़ा।

भारित औसत मांग दरें

8.70
8.50
8.30
8.10
7.90
7.70
7.50

01/06/12 02/06/12 07/06/12 08/06/12 09/06/12 11/06/12 13/06/12 16/06/12 18/06/12 19/06/12 21/06/12 22/06/12

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- उधार लेने वाले वाले बैंकों से मांग के अभाव के कारण बैंकिंग प्रणाली में अतिशय चलनिधि के कारण 31 वीं को मांग दरों में तीव्र गिरावट आई। मांग दरें 30वीं को 8.2% से कमतर स्तर 7.8% पर बंद हुईं।
- बैंकिंग प्रणाणी में निधियों की स्थिर कमी के कारण 5वीं को 5वीं को मांग मुद्रा दरों में और वृद्धि हुई।
- बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की दुर्लभता के बीच उधार लेने वाले बैंकों से नयी मांग के आधार पर 7वीं को एक दिवसीय मुद्रा बाज़ार में भी मांग दरों में तेजी आई।
- एक दिवसीय मांग मुद्रा बाज़ार में मांग दरें सहज रहीं तथा 11वीं को 8.10% के बंद वाले स्तर से थोड़े कमतर स्तर 8.05% पर बंद हुईं।
- अच्छी मांग पर एक दिवसीय मांग मुद्रा बाज़ार में दरों में मज़बूती आई और 15वीं को 8% की तुलना में 8.15% पर बंद हुईं।
- मांग दरें कमोबेश श्रेणीबद्ध रहीं और 7.82% और 8.28% के बीच घटती-बढ़ती रहीं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

17100
16900
16700
16500
16300

21

16100
15900
15700
15500

01/06/12 05/06/12 08/06/12 11/06/12 12/06/12 14/06/12 19/06/12 22/06/12 22/06/12 27/06/12

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जुलाई, 2012